हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड,-याचिकाकर्ता।

बनाम

तारा चंद,-प्रतिवादी।

1987 का नागरिक संशोधन क्रमांक 2777

21 सितम्बर 1988.

मध्यस्थता अधिनियम (1940 का एक्स) - धारा 29 - मध्यस्थ द्वारा भुगतान किए जाने तक ब्याज देना - निर्णय ने न्यायालय का नियम बना दिया - न्यायालय डिक्री की तारीख के बाद ब्याज नहीं देगा - पुरस्कार का प्रभाव - क्या डिक्री के बाद ब्याज देय है।

माना गया कि मध्यस्थता अधिनियम, 1940 की धारा 29 के शब्दों की व्याख्या करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि मध्यस्थ को डिक्री की तारीख से परे ब्याज देने का अधिकार नहीं है। यह शक्ति केवल न्यायालय में निहित है। धारा 29 की कोई अन्य व्याख्या करना क़ानून की भाषा में कुछ जोड़ने के समान होगा और बल्कि शब्दों के साथ हिंसा करना होगा।

अधिनियम की धारा 29 का. डिक्री की तारीख के बाद यदि ब्याज दिया जाना है तो यह केवल डिक्री में शामिल न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है। (पैरा 5 और 9)।

धारा 115 सी.पी.सी. के तहत याचिका श्री जे.एस.खुशदिल पी.सी.एस. के न्यायालय के आदेश के पुनरीक्षण हेतु उप न्यायाधीश प्रथम श्रेणी, चंडीगढ़ ने दिनांक 25 जुलाई 1987 को याचिका खारिज कर दी, क्योंकि मामले का निर्णय श्रीमती द्वारा किया जा चुका है। राज राहुल गर्ग, इसलिए मामले को दोबारा नहीं खोला जा सकता। संपूर्ण पुरस्कार को न्यायालय के नियम के रूप में बनाया गया है। अत: आपत्तिकर्ता की यह आपत्ति टिकाऊ नहीं है कि न्यायालय द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया गया है।

याचिकाकर्ता के वकील एस. सी. कपूर।

मुनीश्वर पुरी, वकील, अश्वनी कुमार बंसल और सुरेश गोयल, वकील, प्रतिवादियों के लिए।

आदेश

नरेश चंद्र जैन, जे.

(1) हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा दायर इस पुनरीक्षण याचिका में इस न्यायालय के निर्णय के लिए कानून का एक महत्वपूर्ण और दिलचस्प प्रश्न खड़ा हुआ है, अर्थात्, क्या मध्यस्थ, कानून में, अंतिम भुगतान तक ब्याज दे सकता है, या है यह कि मध्यस्थ केवल मध्यस्थता अधिनियम की धारा 29 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) के अर्थ के भीतर न्यायालय द्वारा पारित डिक्री की तारीख तक ही ब्याज दे सकता है?

(2) वर्तमान पुनरीक्षण याचिका को जन्म देने वाले तथ्य बहुत ही संकीर्ण दायरे में हैं। मध्यस्थ श्री वी. पी. दुग्गल ने 24 मार्च, 1986 को प्रतिवादी-डिक्री धारक के पक्ष में रुपये की राशि के लिए अपना निर्णय दिया। वसूली तक 4,88,436 प्लस 18 प्रतिशत ब्याज, जिसे श्रीमती राज राहुल गर्ग, उप न्यायाधीश प्रथम श्रेणी द्वारा न्यायालय का नियम बनाया गया था, - 20 अक्टूबर 1986 के अपने फैसले के द्वारा,

निर्णय के अंतिम पैराग्राफ में निम्नलिखित टिप्पणियाँ करते हुए: -

“पूर्व में की गई चर्चा के परिणामस्वरूप, चूँकि आपत्तियाँ टिकाऊ नहीं हैं, इसलिए, मुझे 21 मार्च 1986 के फैसले को न्यायालय का नियम बनाने में कोई झिझक नहीं है और उसी के अनुसार आदेश दिया जाता है। डिक्री शीट

तदनुसार तैयार रहें और फ़ाइल को रिकॉर्ड रूम में भेज दिया जाए।”

(3) जब प्रतिवादी-डिक्री धारक द्वारा निष्पादन किया गया था, तो याचिकाकर्ता-निर्णय ऋणी द्वारा एक आपत्ति दायर की गई थी कि मध्यस्थ के पास की दर पर ब्याज देने की कोई शक्ति नहीं थी

अधिनियम की धारा 29 के मद्देनजर अंतिम वसूली तक 18 प्रतिशत। हालाँकि, आपत्ति को निष्पादन न्यायालय ने इस आधार पर स्वीकार नहीं किया कि मामले को फिर से नहीं खोला जा सकता क्योंकि पूरे फैसले को न्यायालय का नियम बना दिया गया था।

(4) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने जोरदार तर्क दिया कि मध्यस्थ अधिनियम की धारा 29 के मद्देनजर भुगतान तक डिक्री की तारीख से परे ब्याज नहीं दे सकता है और यह केवल न्यायालय है जो डिक्री में ब्याज का आदेश दे सकता है। डिक्री की तारीख से ऐसी दर पर जिसे

न्यायालय उचित समझे, मूल राशि पर भुगतान किया जाना चाहिए जैसा कि पुरस्कार द्वारा तय किया गया है और डिक्री द्वारा पुष्टि की गई है। इस प्रकार, विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि चूंकि न्यायालय ने फैसले की पुष्टि करते समय डिक्री में डिक्री की तारीख से वसूली तक ब्याज के भुगतान का आदेश नहीं दिया था, मध्यस्थ का फैसला निरर्थक और अधिकार क्षेत्र के बिना है। कानून के प्रस्ताव के समर्थन में, वकील ने लाई चंद रॉय बनाम नेरोड कांता गोस्वामी का हवाला दिया है, (1) जिसमें यह माना गया है कि मध्यस्थ के पास डिक्री के बाद ब्याज देने वाला पुरस्कार देने की कोई शक्ति नहीं है और यदि मध्यस्थ ऐसी किसी भी शक्ति का प्रयोग करता है, तो यह अधिनियम की धारा 29 के तहत न्यायालय को प्रदत्त क्षेत्राधिकार का उल्लंघन होगा। आगे यह निर्धारित किया गया है कि जहां मध्यस्थ ने डिक्री के बाद हित के संबंध में कोई निर्णय दिया है, उसकी पुष्टि नहीं की जानी चाहिए।

5) लाई चंद रॉय के मामले (सुप्रा) में निर्धारित कानून के आधार पर और मध्यस्थता अधिनियम की धारा 29 के प्रावधानों की व्याख्या करते समय यह निष्कर्ष अपरिवर्तनीय है कि मध्यस्थ केवल डिक्री की तारीख तक ही ब्याज दे सकता है, उससे आगे नहीं। डिक्री की तारीख (जोर दिया गया)। डिक्री की तारीख से परे, यदि ब्याज दिया जाना है तो यह केवल डिक्री में न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है।

(6) आक्षेपित आदेश के समर्थन में प्रतिवादी डिक्री-धारक के विद्वान वकील ने मिस मोहिंदर कौर कोचर बनाम के रूप में रिपोर्ट किए गए दिल्ली उच्च न्यायालय के तीन फैसलों पर भरोसा किया है।

पंजाब नेशनल बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली और अन्य, (2) पुरी कंस्ट्रक्शन (पी) लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य (3), और मैसर्स ख़ुशी राम जैन एंड कंपनी बनाम नई दिल्ली नगरपालिका समिति और अन्य, (4).

(7) उपर्युक्त न्यायिक घोषणाओं में निर्धारित तथ्यों और कानून को पढ़ने के बाद, मेरा विचार है कि

कोई भी अधिकारी प्रतिवादी की मदद नहीं कर रहा है।

(8) मिस मोहिंदर कौर कोचर के मामले में (सुप्रा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने पैराग्राफ 14 में अपने अंतिम निष्कर्ष में कहा कि यह सही है कि मध्यस्थ के पास केवल पुरस्कार की तारीख से लेकर तारीख तक ब्याज देने का अधिकार है। डिक्रीफी और. इसलिए, वसूली की तारीख तक ब्याज का भुगतान करने का निर्देश तकनीकी रूप से उसकी शक्ति से परे है। उपर्युक्त टिप्पणियाँ करने के बाद व्यावहारिक उपाय के माध्यम से उनके आधिपत्य ने पुरस्कार को गंभीर करना आवश्यक नहीं समझा क्योंकि विद्वान एकल न्यायाधीश ने पुरस्कार को न्यायालय का नियम बना दिया था। व्यावहारिक माप बुनियादी और प्राथमिक कारक था जो अदालत पर निर्भर करता था। इसके अलावा, डिवीजन बेंच विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को अदालत का नियम बनाने के आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रही थी। किसी भी मामले में, लाई चंद रॉय के मामले (सुप्रा) में उनके आधिपत्य का दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट है। पुरी कंस्ट्रक्शन (पी) लिमिटेड के रूप में रिपोर्ट किया गया दूसरा मामला भी मददगार नहीं है क्योंकि जो सटीक प्रश्न मेरे सामने उठा है वह दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष उठाया गया प्रश्न नहीं था। दूसरी ओर, पुरस्कार पर विभिन्न आपत्तियों से निपटने के दौरान, फैसले के अंत में उनके आधिपत्य ने विशेष रूप से माना कि दावेदार तारीख से 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से भविष्य में ब्याज देने का हकदार था। प्राप्ति तक डिक्री। इतना ही नहीं, यह भी देखा गया कि यदि फैसले की तारीख से एक महीने के भीतर राशि का भुगतान नहीं किया गया था, तो डिक्री एक महीने की समाप्ति के बाद निकाली जानी थी। इस प्रकार, दिल्ली उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने पुरस्कार को न्यायालय का नियम बना दिया। दूसरे शब्दों में, दिल्ली उच्च न्यायालय के माननीय एकल न्यायाधीश पुरस्कार पर आपत्तियों की सुनवाई कर रहे थे और आपत्तियों पर निर्णय लेने के समय और पुरस्कार को न्यायालय का नियम बनाते समय, उपरोक्त उल्लेखित निष्कर्ष था रिकार्ड किया गया. यह सटीक बिंदु है जिस पर विद्वान वकील ने तर्क दिया है, जिसका प्रस्तुतीकरण बिल्कुल स्पष्ट है कि अदालत ने डिक्री पारित करते समय डिक्री से परे वसूली तक ब्याज दिया। पुरस्कार को न्यायालय का नियम बनाते समय न्यायालय द्वारा यही नहीं किया गया है। था

वर्तमान मामले में पुरस्कार की पुष्टि करते समय न्यायालय ने उस प्रकार की टिप्पणियाँ कीं जो पुरी कंस्ट्रक्शन (पी) लिमिटेड मामले (सुप्रा) में उनके आधिपत्य द्वारा की गई थीं, निर्णय पूरी तरह से अलग होता और एकल द्वारा निर्धारित कानून का अनुपात दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तत्काल मामले के तथ्यों पर पूरी तरह से लागू होते। पिछले फैसले में लिया गया

दृष्टिकोण, यानी मेसर्स ख़ुशी राम जैन एंड कंपनी का मामला (सुप्रा) बल्कि श्री पुरी, विद्वान वकील द्वारा प्रतिपादित दृष्टिकोण के विपरीत है।

प्रतिवादी. उनके आधिपत्य द्वारा की गई निम्नलिखित टिप्पणियाँ प्रतिवादी डिक्री-धारक के विरुद्ध जाती हैं: -

—

"ब्याज के फैसले का केवल वही आधार बचा है जो दावेदारों के विद्वान वकील के अनुसार, विद्वान मध्यस्थ ने उच्च स्तर पर दिया है। हित से संबंधित दावे 12 के अनुसार, दावेदार ने तर्क दिया कि लंबित मामला और भविष्य का हित विद्वान मध्यस्थ के विशेष क्षेत्र में है। उन्होंने उत्तरदाताओं द्वारा भुगतान रोकने/देरी करने पर 19J प्रतिशत की दर से ब्याज देने के लिए कहा। विद्वान मध्यस्थ ने रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री पर विचार करते हुए निर्णय की तारीख से पहले की अवधि के लिए ब्याज की अनुमति नहीं दी। उन्होंने पुरस्कार की तारीख से पहले महीने के लिए ब्याज की अनुमति देने से भी इनकार कर दिया और उसके बाद भुगतान होने तक 15 प्रतिशत की दर से ब्याज की अनुमति दी गई। प्रथम दृष्टया विद्वान मध्यस्थ द्वारा निकाले गए निष्कर्ष में कोई गलती नहीं दिखती है। हालाँकि, मेरे विचार में विद्वान मध्यस्थ पुरस्कार की तारीख से लेकर भुगतान या उस पर पारित डिक्री तक, जो भी पहले हो, ब्याज दे सकता था। भविष्य के हितों को केवल अदालत द्वारा डिक्री पारित करने से ही ख़त्म किया जा सकता है। इस पहलू पर भी यह नहीं कहा जा सकता कि विद्वान मध्यस्थ ने बिना कार्यवाही किये

क्षेत्राधिकार।"

उपर्युक्त टिप्पणियों में से प्रासंगिक टिप्पणियाँ हैं "हालांकि, मेरे विचार में विद्वान मध्यस्थ पुरस्कार की तारीख से लेकर भुगतान या उस पर पारित डिक्री, जो भी पहले हो, तक ब्याज दे सकता था। भविष्य का ब्याज केवल डिक्री पारित करने वाली अदालत द्वारा ही दिया जा सकता है," प्रतिवादी डिक्री-धारक के विद्वान वकील श्री पुरी द्वारा प्रस्तावित कानून के प्रस्ताव के खिलाफ हैं।

(9) उपर्युक्त टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए। मेरा दृढ़ मत है कि लाई चंद रॉय के मामले में निर्धारित अनुपात (सुप्रा)

वर्तमान मामले के तथ्यों पर पूरी तरह लागू होता है। "शब्दावली

मध्यस्थता अधिनियम की धारा 29 की जब लाई चंद रॉय के मामले में की गई टिप्पणियों के आलोक में व्याख्या की गई (सुप्रा)

इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि मध्यस्थ को डिक्री की तारीख से परे ब्याज देने का अधिकार नहीं है। यह शक्ति केवल न्यायालय में निहित है। धारा 29 की कोई अन्य व्याख्या करना क़ानून की भाषा में कुछ जोड़ने के समान होगा और बल्कि अधिनियम की धारा 29 के शब्दों में ही हिंसा करना होगा।" मेरा मानना है कि मिस मोहिंदर कौर कोचर के मामले (सुप्रा) में दिल्ली उच्च न्यायालय लाई चंद रॉय के मामले (सुप्रा) में निर्धारित अनुपात के खिलाफ नहीं जाता है। किसी भी मामले में, मिस मोहिंदर कौर के मामले (सुप्रा) में दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष तथ्य पूरी तरह से अलग थे और यही सटीक कारण है कि मिस मोहिंदर कौर के मामले (सुप्रा) में निर्णय बाद के दो का आधार नहीं बना। पुरी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड में निर्णय लिमिटेड का मामला (सुप्रा) और मैसर्स ख़ुशी राम जैन 81 कंपनी का मामला (सुप्रा)। दूसरी ओर, जैसा कि ऊपर देखा गया है, उपरोक्त दो मामलों में की गई टिप्पणियाँ लाई चंद रॉय के मामले (सुप्रा) में कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से प्रतिपादित कानून की समर्थक स्थिति के खिलाफ हैं।

(10) ऊपर दर्ज कारणों से, इस पुनरीक्षण याचिका की अनुमति दी जाती है और विवादित आदेश को रद्द कर दिया जाता है। हालाँकि, के मद्देनजर तथ्य यह है कि निर्णय के लिए कानून के जटिल प्रश्न पहले भी उठे थे इस न्यायालय में, पार्टियों को अपनी लागत स्वयं वहन करने के लिए छोड़ दिया गया है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

जसमीत कौर

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(TraineeJudicial Officer)

कैथल, हरियाणा